मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

फरीदाबाद पुलिस में मास्क घोटाला 3
अस्पताल मालिकों से पूछताछ क्यों नहीं 4
ग्रेटर फरीदाबाद झोलाछाप डॉक्टरों की गिरफ्त में 5
सोनिया का सिस्टम, मोदी का सिस्टम 6
श्रीराम अस्पताल में अब एमसीएफ का प्रशासक 8

वर्ष 34 | अंक 27 | फरीदाबाद | 16 मई-22 मई 2021 | फोन-8851091460 | ₹3.00

10 लाख की रिश्वत नहीं मिली तो सीआईए सेक्टर 56 ने 'लूटी' ढाई करोड़ की शराब

सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र पर ठेकेदार का गंभीर आरोप, एक्साइज विभाग ने भी कहा - छापा अवैध

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: सेक्टर 56 सीआईए पुलिस गहरे विवाद में फंस गई है। इसके इंचार्ज रवीन्द्र पर मंजूरशुदा शराब के ठेके से ढाई-तीन करोड़ की शराब लूटने और रिश्वत मांगने का आरोप ठेके के मालिक ने लगाया है। शराब ठेकेदार सरदार मनिन्द्र सिंह ने यह भी कहा है कि वह सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र को हर महीने एक लाख रुपये देता था। आबकारी और कराधान विभाग हरियाणा ने शराब ठेकेदार के अधिकांश आरोपों को सही ठहराया है। एक्साइज विभाग की टीम ने मौके का मुआयना भी किया है। फरीदाबाद पुलिस के अधिकारियों ने पूरी तरह से सारे मामले में चुप्पी साध ली है। हर मामले में बयान देने वाले पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह तक भी सामने नहीं आए।

बिना एक्साइज विभाग कैसे मारा छापा

सेक्टर 56 सीआईए पुलिस ने एसजीएम नगर में राजा चौक पर स्थित मुल्ला होटल के पास मंजूरशुदा शराब के ठेके पर बुधवार को छापा मारा। सीआईए का कहना था कि उसे लॉकडाउन में अवैध रूप से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके से ठेके के दो कर्मचारियों को पकड़ा। यहां तक तो स्थिति ठीक थी लेकिन सीआईए पुलिस के सात लोगों की टीम गुरुवार दोपहर बाद तक भी छापे की कार्रवाई करती रही। इस दौरान पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी को अपने साथ शामिल नहीं किया था। एक्साइज कानून के तहत डीएसपी स्तर के अधिकारी के साथ ही पुलिस किसी ऐसे ठेके पर छापा मार सकती है लेकिन उसके साथ एक्साइज विभाग का कोई अधिकारी होना चाहिए।

इस ठेके पर सीआईए टीम ने 24 घंटे के अंदर आधी से ज्यादा दुकान को खाली कर दिया। ट्रकों में भरकर वहां से शराब अज्ञात स्थानों पर भेज दी गई। इस बीच गुरुवार को मीडिया शराब ठेके पर पहुंच गई और उसने सारा आपरेशन लाइव कर दिया। मीडिया के सामने आए शराब ठेकेदार ने कैमरे के सामने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र पहले सीआईए-30 में था, तब उसे वह हर महीने एक लाख रुपये पूरी सीआईए-30 की ब्रांच के नाम पर पहुंचा रहा था। हाल ही में सेक्टर 56 सीआईए का इंचार्ज बन गया और उसने कुछ दिन पहले डिस्कवरी ब्रांड की पेटी और दस लाख की रिश्वत मांगी। ठेकेदार के मुताबिक उसने रवीन्द्र से कहा कि जब वो हर महीने एक लाख दे रहा है तो दस लाख नहीं दे सकता। रवीन्द्र ने ठेकेदार से कहा कि उसे ऊपर तक पहुंचाने होते हैं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। उसने आरोप लगाया कि रवीन्द्र ने अपने गुर्गों के जरिए उसे मैसेज भिजवाए कि अगर दस लाख नहीं मिले तो उसे बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। रवीन्द्र ने उसे रोलर फेरने की भी धमकी दी। सीआईए ने छापे की कार्रवाई बुधवार को शुरू की थी लेकिन उसने केस गुरुवार को दर्ज किया। ठेकेदार का आरोप है कि उसकी ढाई-तीन करोड़ की शराब रवीन्द्र ने गायब कर दी है और रेकॉर्ड में सिर्फ 1300-1400 पेटियां दिखाई हैं।

रवीन्द्र का काला इतिहास

यह वही रवीन्द्र है जो करीब तीन वर्ष पूर्व सेक्टर-85 क्राइम ब्रांच का इंचार्ज था। उस वक्त यह रात में शराब के नशे में धुत्त होकर बसेलवा कालोनी के एक टैक्सी ड्राइवर से उलझ गया। ड्राइवर भी स्थानीय गूजर था जो इससे दबा नहीं और अपनी टैक्सी लेकर निकल लिया। रवीन्द्र को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उसका पीछा करके बसेलवा कालोनी के आसपास रवीन्द्र ने उसे दबोच लिया और सीआईए सेक्टर-30 में लाकर दो सिपाहियों की मदद से बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। मरणासन्न स्थिति में रवीन्द्र उसे बीके अस्पताल में फेंक कर चला गया था।

मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस को रवीन्द्र व उक्त दोनों सिपाहियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करना पड़ा था और रवीन्द्र फरार हो गया था। इस मुकदमे में तत्कालीन सीआईए इन्सपेक्टर इंचार्ज संदीप मोर को भी लपेटने का प्रयास किया गया था, परन्तु इन्सपेक्टर मोर उन दिनों छुट्टियों पर चल रहे थे इसलिये तत्कालीन सीपी अमिताभ ढिलो ने मोर को छोड़कर उक्त तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। जानकार बताते हैं कि रविन्द्र ने उस वक्त 14 लाख देकर उस ड्राइवर से समझौता करके जान छुड़ाई थी। यहां सवाल यह पैदा होता है जो दागी पुलिसकर्मी महकमे में रहने के लायक ही न हो उसे सीपी ओम प्रकाश सिंह इतना पसंद क्यों करते हैं जो उसे किसी इन्सपेक्टर की पोस्ट पर लगाकर लूटने की खुली छूट दे दें? इतना ही नहीं रवीन्द्र के सामने डीसीपी क्राइम की भी कोई औकात सीपी ने नहीं छोड़ी जब डीसीपी के रोकने के बावजूद रविन्द्र बेखौफ लूटमारी में जुटा रहा। इशारा साफ है कि यह सारी लूट मारी रवीन्द्र अपने आका, सीपी के निर्देशन पर ही कर रहा है।

एक्साइज विभाग ने पोल खोली

एक्साइज विभाग के अफसरों को जब सरकारी ठेके पर छापे की सूचना मिली तो गुरुवार को वो भी ठेके पर पहुंच गए। विभाग के डीटीसी विजय कौशिक ने कैमरे पर कहा कि पुलिस लॉकडाउन में गैरकानूनी शराब बेचे जाने पर केस दर्ज कर सकती है। यह उसका अधिकार है लेकिन किसी सरकारी ठेके से लाखों की शराब जब्त कर लेना नियमों के खिलाफ है।

सीआईए सेक्टर 56 पुलिस ने यह गैरकानूनी काम किया है। हर पेटी का रेकॉर्ड होता है, ठेकेदार ने इसके लिए टैक्स भरा है। विभाग के पास पूरी सूची है। अगर किसी शराब ठेके पर छापा मारना ही है तो सबसे पहले एक्साइज विभाग की टीम और डीएसपी स्तर का अधिकारी छापा मारने वाली टीम के साथ होना चाहिए। सीआईए पुलिस का यह छापा और शराब को जब्त करना अवैध है। वह हमारे रेकॉर्ड में चढ़ी शराब की पेटियों को हजम नहीं कर सकती। उसे हर पेटी का हिसाब देना होगा। कैमरे पर डीटीसी विजय कौशिक ने वहां खड़े सीआईए कर्मी से पूछा कि तुमने किस कानून की किस धारा के तहत यह माल उठाया है। लेकिन वह कोई जवाब न दे सका। हर सवाल के जवाब में वह यही कहता रहा कि आईओ बतायेगा। आईओ कहां है पता नहीं।

डीसीपी क्राईम ने हाथ खड़े कर दिए

सब इंस्पेक्टर रवीन्द्र की इस हरकत की शिकायत करने के लिए एक्साइज विभाग और शराब ठेकेदार ने डीसीपी क्राईम से संपर्क किया। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े करते हुए कहा कि इस संबंध में सीधे पुलिस कमिश्नर से बात की जाए। जब इन लोगों ने कमिश्नर ओ.पी. सिंह से अनेकों बार संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में कुछ सब इंस्पेक्टरों को उनकी उम्मीद से ज्यादा देते हुए उन्हें महत्वपूर्ण थानों, चौकियों और सीआईए का इंचार्ज बना दिया। आमतौर पर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस वाले को सीआईए इंचार्ज बनाने की परम्परा है लेकिन पुलिस कमिश्नर ने रवीन्द्र को सेक्टर 56 में बाकायदा इंचार्ज बना दिया। लेकिन अब उसी रवीन्द्र की वजह से फरीदाबाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। अगर इन आरोपों की जांच उच्चस्तर से हुई तो आरोपों के छींटे पुलिस कमिश्नर पर भी आएंगे। दो दिन बीतने के बाद और इस समाचार के लिखे जाने तक न तो पुलिस कमिश्नर और न ही पुलिस प्रवक्ता ने कोई बयान इस मामले में जारी किया है। मीडिया में इस गंभीर घटना के सामने आने के बावजूद पुलिस अफसरों का इस तरह चुप्पी साधना काफी रहस्यमय होता जा रहा है।

वायरल होने से खफा रवीन्द्र ने टार्चर भी किया

पूरा मामला उच्चाधिकारियों, मीडिया व पूरी पब्लिक के सामने उजागर होने से बौखलाए रवीन्द्र ने वीरवार देर रात मनिन्द्र व उसके भाई को उठवा लिया और अपनी चौकी सेक्टर-56 ले गया। वहां उसके ऊपर मूसली फेरी और उनका मुंह पानी में डुबोया और उनको कई तरह से टॉर्चर किया। इसके बाद देर रात उनके परिजनों को बुलाकर डरा धमकाकर उनसे कोरे कागजों पर दस्तखत कराये व उनसे वायदा लिया कि वे इस सारे कांड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही मीडिया में जायेंगे। सब इंस्पेक्टर स्तर के इस अधिकारी ने इस तरह कानून को ताक पर रखकर गुंडागर्दी करने का साहस यूं ही नहीं आया। जाहिर है कि इसको उच्चस्तरीय संरक्षण प्राप्त है।

सड़क चौड़ाने के नाम पर वृक्षों की बलि

फरीदाबाद (म.मो)। न जाने क्यों भाजपा सरकार को हरे-भरे वृक्षों से इतनी भारी दुश्मनी है। शायद वे चाहते हैं कि जनता को न तो शुद्ध हवा मिल सके और न ही प्रदूषण कम हो।

सेक्टर 7-8 की विभाजक सड़क गुड़गांव नहर से पार करते हुए सैक्टर-3 होते हुए तिगांव रोड तक जाती है, इस पर लगे पचासों पेड़ बीते पखवाड़े काट डाले गये। ये पेड़ नहर पार के सेक्टर 3 क्षेत्र में थे। इनमें से कुछ पीपल तथा बड़ के वृक्ष 60-70 वर्ष पुराने थे। सेक्टर तीन निवासी अनिल तेवतिया ने बताया आठ वृक्ष तो उनके दादा स्वर्गीय बलबीर सिंह (सीही के पूर्व सरपंच द्वारा 1950 के दशक में लगाये थे)। पूरे परिवार ने इन वृक्षों को अपने बच्चों की तरह पाला था। आज उन्हें, कटता देख सारे परिवार के आंसू छलक आये। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काफी विरोध भी किया। स्थानीय विधायक एवं मंत्री मूलचंद शर्मा से भी गुहार लगाई, परन्तु सड़क चौड़ाने एवं तथाकथित विकास के नाम पर उन्होंने भी इस अनुरोध को ठुकरा दिया।

तेवतिया ने बताया कि इन तमाम पेड़ों की कीमत सरकार को मात्र 56 हजार रूपये मिली। जबकि दसियों वृक्ष तो ऐसे थे जिनकी अकेले-अकेले ही कीमत 50 हजार से कम न थी, यानी कि इस ठेके में भी घोटाला हो गया। इसके अलावा उस सड़क को इतना चौड़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं कि इतने पेड़ काटे जाते। पेड़ों को बचाकर भी आवश्यक चौड़ाई बढ़ाई जा सकती थी। परन्तु जब जनता एवं वृक्षों से ही दुश्मनी हो तो ऐसा क्यों किया जाये और फिर पेड़ काटने से जब लाखों का घोटाला किया जा सके तो उन्हें छोड़ने का प्रश्न ही नहीं।

इस तरह का घिनौना खेल केवल सेक्टर-3 में ही नहीं खेला जा रहा बल्कि बदरपुर बार्डर से लेकर गुड़गांव नहर के साथ-साथ चले आ रहे बाई पास रोड पर तो इससे भी भयंकर खेल खेला जा रहा है। बाईपास को चौड़ा करने के नाम पर सेक्टरों के पीछे की पूरी ग्रीन बेल्ट ही उड़ाई जा रही है। इसमें लगे 30-40 वर्ष पुराने हजारों वृक्ष काटे जा रहे हैं।

सेक्टर-17 के साथ लगता रोज गार्डन व नर्सरी पूरी तरह से तबाह की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन बेल्ट सेक्टर वासियों को दी जा चुकी थी उसे बचाया नहीं जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था यदि भाजपा सरकार की नीयत साफ होती तो, उपलब्ध पुख्ता जानकारी के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई नहर की तरफ खाली पड़ी सरकारी जमीन की तरफ बढ़ाई जानी थी, परन्तु उस तरफ स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री गूजर के आशीर्वाद से कुछ लोगों ने बड़े-बड़े शोरूम खड़े कर रखे हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। केवल इन अवैध निर्माणों को बचाने के लिये सड़क की लाइनिंग बदली गयी है। जानकारों का मानना है कि यह रद्दों-बदल मुफ्त में ही नहीं हो गयी है। इसके लिये हुडा के अफसरों व राजनेताओं के साथ अच्छा-खासा लेन-देन हुआ है।

गौरतलब यह भी है कि जिस बाईपास को इतना चौड़ाने की तैयारी की जा रही है, उतने की आवश्यकता ही नहीं है। शहर के बीचो-बीच से गुजरने वाली मथुरा रोड को 6 लेन बनाने के बाद यातायात की समस्या काफी हल हो चुकी है, कमी है तो सर्विस रोड की जिसकी वजह से पुलों के नीचे जाम की स्थिति बनी रहती है।

हरे-भरे वृक्षों से दुश्मनी निभाते हुए भाजपा सरकार ने नई दिल्ली के बीचों-बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिये भी 100-100 साल पुराने हजारों वृक्षों की बलि चढ़ा दी गयी। इसी तरह उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग के नाम पर तो वहां जंगलों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है।

दरअसल सड़क मंत्री नितिन गडकरी को सड़क निर्माण का धंधा इतना रास आ रहा है कि उनका बस चले तो पूरे देश का सफाया करके सड़क ही सड़क बना दें क्योंकि इसमें खर्चा तो ठेकेदार कम्पनियां करती हैं जिसकी भारी भरकम वसूली टोल-टेक्स द्वारा की जाती है और मोटा कमीशन राजनेताओं के गिरोह तक आराम से पहुंच जाता है। इसी तर्ज पर नगर निगम व 'हूडा' वालों को भी सड़क निर्माण कार्य बहुत भाता है।